

INDEX विशेष सूची

1	Bharat Ki Baat, Sabke ke Saath भारत की बात, सबके साथ	10	Gram Swaraj Abhiyan ग्राम स्वराज अभियाल
2	India's growth rate is projected to leapfrog! भारत के विकास दर में बढ़त जारी!	11	Study In India Portal launched "ਮਟਤੀ इन इंडिया" ਧੀਟੀਰ ਗੱਰਚ
3	India-China informal summit भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन	12	Last mile delivery of Rural Electrification ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा
4	Engaging the diaspora in Sweden स्वीडन में भारतीय समुदाय को संबोधन	13	Satyagraha to Swachhagraha सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह
5	Atal Pension Yojana अटल पेंशन योजना	14	DefExpo 2018 डिफेंस एक्सवो 2018
6	PM Modi's interaction with CWG 2018 medalists राष्ट्रमंडल खेलों 2018 के पदक विजेताओं से पीएम मोदी की बातचीत	15	Habitations covered under PMGSY पीएमजीएसवाई के तहत सड़क संपर्क से जुड़ रही बसावटें
7	Boost to tribal welfare in India देश में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा	16	ISRO launches IRNSS-11 इसरो के आईआरएनएसएस -1 का सफल प्रक्षेपण
8	Ordinance on Death Penalty for rapits of girls below 12 years बिट्टियों से रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा पर अध्यादेश	17	PM Modi interaction with MUDRA beneficiaries मुद्रा लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत
9	Schemes launched on Ambedkar Jayanti अम्बेडकर जयंती पर योजनाओं का शुभारंभ	18	Fugitive Economic Offenders Ordinance भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर अध्यादेश

EXCLUSIVE FOCUS

PM Modi presents his vision for 'New India' at Bharat Ki Baat, Sabke Saath

The rising global stature of India is evident from the soaring welcome received by PM Narendra Modi during his international visits. In the extraordinary and historic location of Westminster Hall in London, PM Narendra Modi presents his vision and trajectory of 'New India'. Addressing the Indian diaspora in London in the landmark event titled 'Bharat ki Baat, Sabke Saath', PM Modi asserted that people have more expectations from the Government because they know that the Government can deliver. People know when they say something, the Government will listen and do it.



What did the PM say?

- 'Besabri' is not a bad thing. If a person has a cycle, a person aspires a scooter. If a person has a scooter, a person aspires a car. It is nature to aspire. India is getting increasingly aspirational
- Mahatma Gandhi turned the struggle for independence into a mass movement. In the same way, development should now become a 'Jan Andolan'
- Democracy is not any contract or agreement, it is about participative governance
- Democracy cannot succeed without constructive criticism. I want this Government to be criticised. Criticism makes democracy strong
- We believe in peace. But we will not tolerate those who like to export terror. We will give back strong answers and in the language they understand
- Hard work, honesty and the affection of 125 crore Indians are my assets
- We have a million problems but we also have a billion people to solve them
- We live in a technology driven society today.
 In the era of artificial intelligence, we cannot refrain from embracing technology
- I have lived in poverty, I know what it is to be poor and belong to the backward sections of society. I want to work for the poor, the marginalised and the downtrodden
- I was not born with an aim to be in history books. Remember our country and not Modi







एक्सक्तूसिव फोक्स:

"भारत की बात, सबके साथ" में झलका 'न्यू इंडिया' को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नवाचार, उद्यम, विकास और निवेश के क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस संबंध में उठाए गए असाधारण कदमों के बारे में भारतीय समुदाय से बातचीत की, जिसमें उन्होंने न केवल भारत के विकास कहानी बताई बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद का भी जिक्र किया है। लंदन में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम 'भारत की बात, सबके साथ' में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार से लोगों की उम्मीद में वृद्धि हुई है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सरकार यह कर सकने में सक्षम है। लोग जानते हैं कि जब वे कुछ कहते हैं, तो सरकार सुनेगी और जरूर करेगी।



प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

- मेरी दृष्टि से बेसब्री गलत नहीं है और आपने देखा होगा, जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है स्कूटर है तो मन करता है यार चार पहिया आ जाए तो अच्छा है।
- महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को जन आंदोलन में बदल दिया। उसी तरह, विकास भी अब 'जन आंदोलन' बनना चाहिए।
- लोकतंत्र कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं, ये जनभागीदारी का काम है।
- सकारात्मक आलोचना के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार की आलोचना की जाए। आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
- हम शांति में विश्वास करते हैं। लेकिन हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सीमा पार से आतंक को बढ़ाते हैं। हम उन्हें उन्ही की भाषा में मुँहतोड़ जवाब देंगे।
- नेरी पूँजी है कठोर परिश्रम, प्रमाणिकता और सवा सौ करोड़ लोगों का प्यार।
- हमारे पास लाखों समस्याएं हैं लेकिन उसके समाधान के लिए हमारे पास अरबों लोग भी हैं।
- हम आज एक प्रौद्योगिकी संचालित समाज में रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के युग में, हम प्रौद्योगिकी को अपनाए बगैर नहीं रह सकते हैं।
- में गरीबी की जिंदगी को जी करके आया हूं। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती है, वो मैं देखकर आया हूं। मैं गरीबों और कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहता हूं।
 - इतिहास में नाम अंकित करना मेरा लक्ष्य नहीं, मैं उसी तरह जैसे मेरे सवा सौ करोड देशवासी।



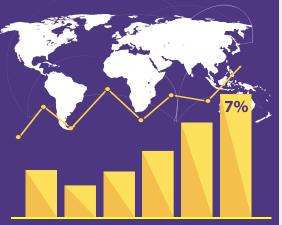




TOP STORIES

India's 7 % projected growth rate expected to grow manifold-Asian Development Bank report

India's growth trajectory reflects that the government led by PM Narendra Modi is committed to its vision of Transforming India. The cohesive and inclusive growth can be attributed to the Government's pro-people and proactive approach in enabling Ease of Living for ciizens. The Government is working towards realizing the vision for New India and has nurtured an ecosystem where the economy is primed for growth and where growth promotes all round development.



Highlighting government endeavours like Make in India, Digital India and policy approaches that seek to remove red tape and pave a smooth path for the investors as could be corroborated from the latest 'Ease of Doing Business' report, the government is surging ahead with reforms that seeks to transform India.

The chief economist of the Asian Development Bank lauded India's projected growth over 7% for the current fiscal and called it 'amazingly fast'.



Another important facet mentioned by the chief economist is that India's growth is further sustained by the domestic market where export forms one of the cornerstones. In this context apart from pitching India as an attractive destination for investment and entrepreneurship, PM Modi had undertaken crucial structural reforms including demonetisation and the roll out of the Goods and Service Tax (GST) that has not only resulted in strong growth in private consumption and services but led to a recovery in private investment.

Lastly, highlighting the need for tapping the broadening market, the report has also mentioned recent progress in India's service sector that has witnessed an increase in job creation has also been instrumental in accelerating the pace of economic growth.

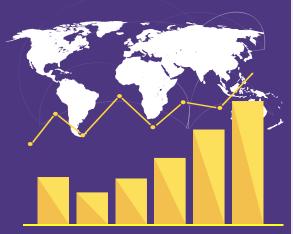




प्रमुख समाचार

भारत की अनुमानित विकास दर 7% रहेगी : एशियाई विकास बैंक

देश के विकास में लगातार हो रही वृद्धि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की भारत में बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। देश के समावेशी विकास की दिशा में सरकार नागरिकों की जरुरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर पूरी दृढ़ता से कार्य कर रही है ताकि नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जा सके। न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, जो समग्र विकास को बढ़ावा दे।



मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रयासों और लाल फीताशाही खत्म कर निवेशकों की राह आसान करने के लिए सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की नवीनतम बिजनेस रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है। देश में बदलाव के उद्देस्य से सरकार उन सुधारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है।

सरकार के इसी दृष्टिकोण की झलक एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री की नवीनतम घोषणा में मिलती है जिसमें उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। मुख्य अर्थशास्त्री भारत की तेज विकास दर की सराहना करते हुए कहते हैं कि भारत की यह वृद्धि दर, वास्तव में अद्भुत है।



मुख्य अर्थशास्त्री ने भारत के घरेलू बाजार के विकास को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। इस संदर्भ में भारत को निवेश और उद्यमशीलता का एक आकर्षक गंतव्य स्थल बताने के साथ—साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए हैं। इससे न केवल निजी खपत और सेवाओं में मजबूत वृद्धि हुई है बिल्क निजी निवेश में भी सुधार हुआ है।

अंततः आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बाजार के व्यापक दोहन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ—साथ भारत के सेवा क्षेत्र में हालिया प्रगति ने भी आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।





PM Narendra Modi - President XI Jinping informal summit : Moving towards a new equilibrium in India - China understanding



The recently concluded informal summit between PM Narendra Modi and the President of People's Republic of China Xi Jinping at Wuhan in China is a promising step towards enhancing the relationship between the countires. During the summit, both the leaders exchanged their views on overarching issues of bilateral global importance and to elaborate their respective visions and priorities for national development in the context of the current and future international relations.

Highlighting the emergence of India and China as two large economies with both strategic and decisional autonomy, the leaders stated that their decisions have both regional and global implications.

In this context, a common vision for 'Asian Century' that will entail both a peaceful, stable and balanced Asia along with economic growth and development could only be enhanced if both India and China work in collaboration . An apt characterization of the warming up of the bilateral ties could be noticed in their effort to strengthen the 'Closer Development Partnership ' in a mutually beneficial and sustainable manner in pursuit of both national modernisation and greater prosperity for its people .

Key takeaways from the summit:

- To ensure peace and stability along the Indo-China border and prevent any future flare-ups India and China agreed to intensify the work of the Special Representatives on the India -China boundary question and urged them to intensify their efforts to seek a fair, reasonable mutually acceptable settlement.
- Agreed to collaborate on facilitating sustainable solutions for global challenges including climate change, sustainable development, food security etc
- Emphasized on building an open, multipolar, pluralist and participatory global economic order
- Lastly recognized the common threat posed by terrorism and reiterated their strong condemnation of and resolute opposition to end terrorism in all its forms.

- 2 Secondly, the two leaders agreed to push forward bilateral trade and investment in a balanced and sustainable manner by taking advantage of complementarities between their two economies
- Both the leaders recognized that India and China as two major countries have an intersection of interests and history and thereby agree to strengthen strategic communication through greater consultation on matters of common interest
- The leaders also affirmed their action to take a joint lead in offering innovative and sustainable solutions to challenges faced by mankind in 21st century including combating diseases, coordination action for disaster risk reduction and mitigating, addressing climate change and ushering in digital empowerment



भारत और चीन एक संतुलित संबंध की ओर अग्रसर



हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रपित शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों के आदान—प्रदान एवं दोनों देशों के बीच के संबंध को सामान्य बनाने हेतु वुहान में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों ने वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में अपने—अपने देशों के राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण पर विचार—विमर्श किया।

दोनों देशों ने स्वीकार किया कि दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं एवं महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्तियों के रूप में भारत और चीन का उदय क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण है।

दोनो देशों ने सम्मिलित रूप से माना कि द्विपक्षीय संबंधों का समुचित प्रबंधन क्षेत्रीय विकास एवं स्थिरता के लिये उपयुक्त रहेगा और एशिया की सदी के निर्माण के लिये अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेगा। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय आधुनिकीकरण और अपने लोगों को अधिक समृद्ध बनाने के लिये एक करीबी विकासात्मक साझेदारी को परस्पर लाभकारी और स्थायी तरीके से सशक्त बनाने का निश्चय किया।

शिखर सम्मेलन के मुख्य अंश:-

- दोनों देशों ने भारत—चीन सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी आपसी तनाव से बचने हेतु विशेष प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे काम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और उनसे एक न्यायोचित, समुचित और परस्पर रूप से स्वीकार्य समझौते को हासिल करने के लिये उनकी कोशिशों तेज करने का आग्रह किया।
- 3 दोनों नेता दोनों देशों के बीच मौजूद लाभकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुये द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को एक संतुलित और स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुये।
- 5 दोनों नेताओं ने एक खुले, बहुध्रुवीय, बहुलवादी एवं भागीदारी पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के पर सहमति जताई।
- अंततः प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपित शी ने आतंकवाद के सम्मिलित खतरे को पहचाना और आतंकवाद के सभी प्रकारों और सभी रूपों के प्रति अपने प्रबल प्रतिरोध और जोरदार भर्त्सना को फिर से दोहराया।

- 2 दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि दो महत्वपूर्ण देशों के तौर पर भारत और चीन के व्यापक और परस्पर जुड़े हुये क्षेत्रीय और वैश्विक हित हैं। दोनों नेता साझा हित के सभी विषयों पर अधिक चर्चा के जरिये रणनीतिक संवाद को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुये।
- 4 वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, स्थायी विकास और खाद्य सुरक्षा और अन्य चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिये संयुक्त रूप से योगदान देने पर भी दोनों देश सहमत हुये।
- 6 दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त कि भारत और चीन को 21वीं सदी में मानव जाति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये आपस में हाथ मिला लेने चाहिये और दोनों देशों को मिल कर रोगों का मुकाबला, आपदाओं के खतरे को कम करने के कार्यों में समन्वय, जलवायु परिवर्तन से निपटना और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए।





PM Modi engages with the Indian diaspora in Stockholm

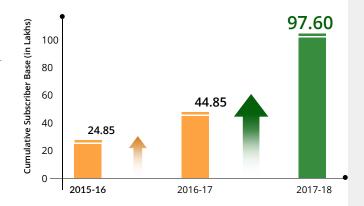
Key Takeaways from PM Modi's Address:

- India is going through a great transformation today
- In the last four years, Government has worked towards a developed and inclusive India
- Government is focusing on 'Ease of Living'
- Through initiatives such as the International Yoga Day, efforts are being made to accelerate India's emergence as a global thought leader
- Technology is bringing about transparency and accountability in governance



Increase in subscriber base to 97.60 lakh under the Atal Pension Yojana

The Government of India is extremely concerned about the old age income security of the working poor throughout its course. As of April 12, 2018 the total number of subscribers under Atal Pension Yojana has crossed 97.60 lakhs.



PM Narendra Modi interacts with Gold Coast CWG medallists

PM Narendra Modi interacted with the medal winners of the Gold Coast Commonwealth Games where he lauded their achievements and also exuded his compliments to those who could not win laurels but have performed creditably. Citing examples of Mary Kom and Pullela Gopichand, the PM also reiterated the benefit of yoga apart from talent, training, concentration and hard work that is important for both the present and future sportspersons of the country.







पीएम मोदी ने स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

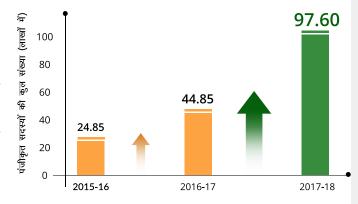
भारतीय समुदाय को पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य अंश इस प्रकार हैं: —

- 🛶 भारत आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- पिछले चार वर्षों में सरकार ने एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया गया है।
- ── नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार विशेष
 ध्यान दे रही है।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों के जिरये ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं तािक भारत एक बार फिर विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे।
- प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता
 और उत्तरदायित्व आ रहा है।



अटल पेंशन योजना के पंजीकृत सदस्यों की संख्या 97.60 लाख के पार

गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। 12 अप्रैल, 2018 तक, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 97.60 लाख के पार हो गई है



गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी तथा उन खिलाड़ियों को भी बधाई दी जो पदक जीत पाने में असफल रहे, परन्तु उन्होंने विश्वसनीय प्रदर्शन किया। मैरी कॉम और पुलेला गोपीचंद का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभा के अलावा आज खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, एकाग्रता, किन मेहनत और मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने योग के फायदों का वर्णन किया।







Van Dhan Vikas Kendras to expand in Tribal Districts across India

An important thrust of the government led by PM Narendra Modi has been to empower the lives of the poor through sustainable livelihood opportunities. In this regard, PM Modi described that the tribal communities act as a great force for national development and highlighted the need for developing strategies to foster a spirit of inclusive and comprehensive growth among the tribal communities.



It was during the occasion of Ambedkar Jayanti, that PM Modi put forward the idea of converging "Jan Dhan, Van Dhan and Gobar-Dhan" to empower tribal community. This comes as a remarkable move which will usher in overall welfare for the tribal populace.

In this context, the Ministry of Tribal Affairs has proposed to expand the Van Dhan Vikas Kendras in tribal districts across the countries. The aim of the establishment of these Kendras is to provide skill upgradation and capacity building training to increase the incomes of tribals. The Ministry stated that the Van Dhan Vikas Kendras will be an important milestone in economic development of the tribals involved in collection of Minor Forest Produce (MFP) by helping them in optimum utilisation of natural resources. Further Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED) will provide the training and the technical support.



The initiative has been designed to mainstream the tribal community by promoting primary value addition to MFP at grassroots level which would form the basis for transforming the rural and tribal economy in the future.





देश के जनजातीय जिलों में वन-धन विकास केन्द्रों का होगा विस्तार

गरीबों के सशक्तिकरण हेतु पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार का विशेष जोर देश के ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं पर रहा है। इस संबंध में पीएम मोदी का मानना है कि राष्ट्रीय विकास के लिए आदिवासी समुदाय एक बड़ी शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विकास हेतु रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर डालते हुए वे कहते हैं आदिवासी समुदाय हमेशा समावेशी और सतत विकास की भावना को बढ़ावा देते हैं।



अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय के लिए जन धन, वन धन और गोबर—धन योजनाओं समेत कई योजनाओं को एकजुट करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं के सम्मिलन से पूरी जनजातीय आबादी का समग्र कल्याण होगा।

इस संदर्भ में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केन्द्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य आदिवासियों की आय बढ़ाने हेतु कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि वन धन विकास केंद्र प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु वनोत्पाद एकत्रित करने वालों और कारीगरों के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आगे इन्हें ट्राइफेड (TRIFED) के माध्यम से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।



इस पहल को जनजातीय समुदाय को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर एमएफपी को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन किया गया है जो भविष्य में ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का आधार तैयार करेगा।





India introduces ordinance for death penalty for rapists of girls below 12 years - A step towards women safety

Time and again, Prime Minister Narendra Modi has reiterated the importance of providing a safe and secure environment to the women of the country. Moreover, the PM has further asserted that crimes against women should be comprehended and dealt in a sensitive manner.



The Government has envisaged a macro-level approach, to not only bring the perpetrators of such crimes to justice, but also enable in creating an overall safe and secure environment for women including minors in the society.

In this context, the promulgation of an ordinance by the Centre to amend the Indian Penal Code (IPC), the Evidence Act, Code of Criminal Procedure and Protection of Children from Sexual Offences (POSCO) Act, includes the provision of capital punishment or death penalty for convicted rapists of children below the age of 12 years as of April 21, 2018 is instrumental towards meting out justice to the women. This will further aid in creating conducive conditions for an overall betterment of the women in the society.

Under the Criminal Law (Amendment) Ordinance 2018, some of the components have been laid out below which encapsulates both the significance of the law and the endeavour of the government to impart justice to its women citizens and thereby accelerate the progress of our society. Some of the measures which stand amended are as follows:-

- 1 The ordinance stipulates stringent punishment for perpetrators of rape particularly of girls below 16 and 12 years. Death sentence has been provided for rapists of girls under 12 years.
- 2 The minimum punishment in case of women has been increased from rigorous imprisonment of seven years to 10 years, extendable to life imprisonment.
- In case of rape of a girl under 16 years, the minimum punishment has been increased from 10 years to 20 years, extendable to imprisonment for rest of life, which means jail term till the convict's "natural life".
- The punishment for the gang-rape of a girl under 16 years of age will invariably be imprisonment for the rest of the life of a convict.
- Moreover the ordinance also prescribes the formation of new fast track courts that that will be set up to deal with rape cases and special forensic kits will be provided to all police stations and hospitals in the long run.
- 6 Lastly the ordinance also recommends the mandatory completion of rape incidents within two months and advised that trials should be completed within two month.





महिला सुरक्षा की दिशा में कदम: 12 साल से कम उम्र के बद्वियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान

एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं और बिच्चियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले को बेहद सूझबूझ के साथ संवेदनशील और मानवीय तरीके से निपटाया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से तभी सफल हो पाएगा जब समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से इस दिशा में प्रयास करें।



समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मूल कारणों की समझ और इसकी संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरकार ने इस तरह के अपराध करने वाले अपराधियों को न केवल कड़ी सजा देने पर विचार किया है बल्कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समग्र सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में भी एक कदम उठाया है।

इस संदर्भ में, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश लाया गया है जिसके तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दोषी बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान किया गया है। 21 अप्रैल, 2018 को लिया गया यह निर्णय महिलाओं के समग्र उत्थान हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने में मदद करेगा।

आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के जिए महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा व न्याय प्रदान करने के लिए कानून को और सख्त बनाया गया है तथा इस दिशा में सरकार के सशक्त प्रयास से उनका समग्र विकास हो सके। अध्यादेश के तहत कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

- अध्यादेश के मुताबिक 16 वर्ष से कम और विशेष रूप से 12 वर्ष से कम उम्र की लड़िकयों के बलात्कार के अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।
- 2 किसी महिला के साथ बलात्कार के संदर्भ में न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष के कारावास किया गया है जिसे बढ़ाकर उम्र कैद किया जा सकता है।
- 3 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में, न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़कर 20 साल हो गई। जिसे बढ़ाकर उम्रकेंद में बदली जा सकती है, जिसका अर्थ है कि दोषी के "प्राकृतिक जीवन" तक जेल की अवधि।
- 4 16 साल से कम उम्र के लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषियों को सजा, हमेशा शेष जीवन के लिए कारावास होगी।
- अध्यादेश में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके त्वरित निपटान अदालतों के गठन की बात कही गई है। सभी पुलिस थाने और अस्पतालों में विशेष फारेंसिक किट उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
- 6 अंततः रेप के मामले में जांच को 2 महीने में खत्म करना होगा। ट्रायल पूरा करने के लिए 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है।





On the occasion of Ambedkar Jayanti , Government launches initiatives to empower the lives of the poor

The Union Budget 2018 laid the foundation for the world's largest healthcare programme, Ayushman Bharat. The programme was officially launched by PM Narendra Modi on Ambedkar Jayanti with the inauguration of a health centre in Bijapur, Chattisgarh.

The PM also launched 'VAN DHAN' Yojana aimed towards the development of tribal communities. Through video conferencing he dedicated the Bhanupratappur - Gudum railway line to the nation. In the areas affected by the left-wing extremism, he laid the foundation stone for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), water supply scheme of Bijapur and two bridges.







On the occasion of Ambedkar Jayanti, PM Modi launched the Gram Swaraj Abhiyan as a commitment towards achieving prosperity and happiness of all villages.

The implementation and monitoring of activity of scheme will broadly be aligned for achieving Sustainable Development Goals (SDGs) with main thrust on Panchayats under Mission Antyodaya and 115 Aspirational district identified by NITI Aayog.



The initiative targeted at achieving saturation of eligible households/persons in the identified 21,058 villages; under seven flagship pro-poor programes, namely Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Saubhagya, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Mission Indradhanush.



Ujjwala Yojana

(launched on May 1, 2016)

Target - 5 crore originally now, 8 crore by March 2020, Achievement so far:
3.57 crore connection release



Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)

(September, 2017)

Target - 3.7 crore, Achievement- 39 lakh electrified, 3.3 crore by March 2019.



Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

(May 9, 2015)

Coverage so far- 5.33 crore beneficiaries enrolled,
Achievement- 90,082 claims
Rs 1,802 crore disbursed.



Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana

(May 9, 2015)

Coverage - 13.49 crore enrolled,

Achievement - 16,469 claims
of Rs 328 crore disbursed



Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (March 2015)

Target- Universal Access to banking facilities, March 2015- 14.71 crore accounts, March 2018- 31.44 crore accounts, **Achievement- Rs 78,404 crore** mobilised, 4,675 life insurance claims paid





अम्बेडकर जयंती के अवसर पर गरीबों के सशक्तिकरण के लिए दो नई पहल का शुभारंभ

आयुष्मान भारत

केंद्र सरकार के कदम एवं पहल समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। 14 अप्रैल, 2018 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत को लॉन्च किया और यहाँ एक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन कर "सबका साथ, सबका विकास" की दिशा में एक और पहल की है।

इसी दिन प्रधानमंत्री ने वन धन योजना भी लॉन्च की जिसका उद्वेश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है। यहाँ प्रधानमंत्री ने एक महिला को अपने हाथ से चप्पल पहनाकर सबका दिल जीत लिया। वीडियो कांफ्रेसिंग के जिरये प्रधानमंत्री ने भानुप्रतापपुर—गुडम रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण तथा बीजापुर में जलापूर्ति योजना एवं दो पुलों का शिलान्यास किया।



इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान सुनिश्चित करेगा कि पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी विकास पहलों का लाभ समाज के निर्धन एवं वंचित वर्गों तक पहुंचे।





अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की और सभी गांवों की समृद्धि और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई।

मिशन अत्योदय के तहत सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के उद्देश्य से योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी को मुख्य रूप से पंचायत के जिए किये जाने पर जोर दिया और नीति आायोग द्वारा 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है।



इस अभियान के तहत देशभर के 21,058 गांव में जन कल्याण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से गरीब कल्याण से जुड़ी उज्ज्वला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उजाला, प्रधानमंत्री जन—धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शत प्रतिशत लागू करने पर जोर दिया जाएगा तथा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।



उज्ज्वला योजनाः

(1 मई, 2016 को लॉन्च) लक्ष्य — पहले 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का वितरण का लक्ष्य, अब मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगें

> उपलब्धि अब तकः 3.57 करोड़ कनेक्शन वितरित



सहज बिजली हर घर योजना (सोभाग्य)

(सितंबर, 2017) लक्ष्य – 3.7 करोड़, उपलब्धि – 39 लाख घर विद्युतीकृत, मार्च 2019 तक 3.3 करोड़ घर विद्युतीकृत हो जाएंगें।



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति clek; ktuk

(9 मई, 2015)

अब तक कवरेज— 5.33 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत, उपलब्धि — 90082 दावों के लिए 1802 करोड़ रुपये दिए गए।



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(9 मई, 2015)

अव तक कवरेज — 13.4 9 करोड़ पंजीकृत, उपलब्धि — 328 करोड़ रुपये के 16,469 दावों के लिए 328 करोड़ रुपये का वितरण



प्रधानमंत्री जन धन योजना (मार्च, 2015)

लक्ष्य — सभी तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाना, मार्च 2015 तक 14.71 करोड़ खाते, मार्च 2018 तक 31.44 करोड़ खाते, उपलब्धि — 78,404 करोड़ रुपये जमा किए गए, 4,675 जीवन बीमा दावों का भुगतान





Study In India portal launched to attract students from across the globe

With an aim to attract bright young minds from across the globe, the 'Study in India program' was launched the 'Study in India 'portal (www.studyinindia.gov).

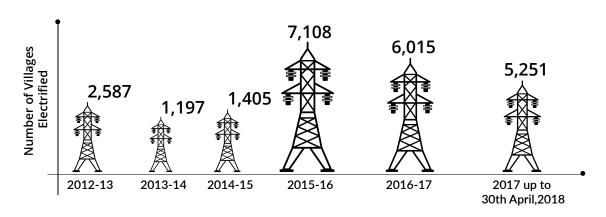
Takeaways from the initiative:-

- 'Study in India' website, a single window covering all aspects relating to study in Indian institutions launched on April 18, 2018
- The website to supported by an App and Helpline Number
- Focus on students from 30 countries across Asia, Africa, Commonwealth of Independent States and Middle east
- 160 Indian Institutions offered 15,000 seats in 1st round and Indian institutions having 3.26 score on NAAC and NIRF rankings included under the program



Powerful India: Last mile delivery of Rural Electrification!

28th April 2018 will be remembered as a historic day in realizing the vision of "Antyodaya". On this day, Government led by PM Narendra Modi achieved the feat of electrifying the last un-electrified village out of the 597,464 census villages across India. Rural electrification of the remaining 18,452 was one of the most ambitious goals set by the Government in 2014. A new chapter has been scripted in journey towards building New India as every village of India now has access to electricity. The last unelectrified village to be electrified was Leisang village in the Senapati district of Manipur and the target has been completed 12 days ahead of the deadline.







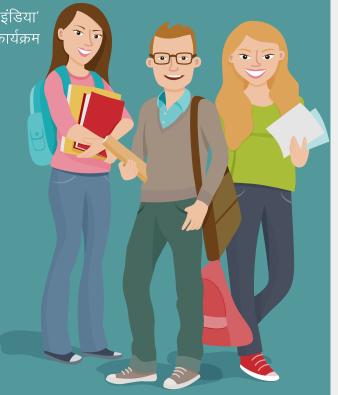


विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल लॉन्च

प्रतिभावान विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल (www.studyinindia.gov.in) लॉन्च करके 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

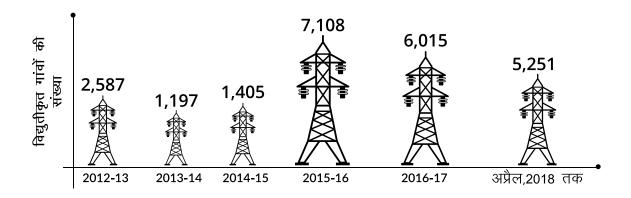
इस पहल के प्रमुख बिंदुः

- 18 अप्रैल, 2018 को 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल लॉन्च, जो विदेशी विद्यार्थियों के लिए भारत में अध्ययन से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करने वाली एकल खिड़की है।
- 🗕 एक ऐप तथा हेल्पलाइन नम्बर समर्थित वेबसाइट।
- 30 एशियाई, अफ्रीकी, मध्य पूर्व तथा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) देशों के विद्यार्थियों पर फोकस।
- 160 संस्थानों ने पहले दौर में 15,000 सीटों की पेशकश की। इस कार्यक्रम में एनआईआरएफ रैंक वाले तथा एनएएसी मान्यता प्राप्त
 3.26 स्कोर वाले संस्थान शामिल किए गए हैं।



सशक्त भारतः अविद्युतीकृत गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा

28 अप्रैल 2018 को "अंत्योदय" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने देश के आखिरी अविद्युतीकृत गाँव में बिजली पहुँचा कर देश के 597,464 गाँवों को रौशन करने की उपलब्धि हासिल की। मौजूदा सरकार के आने तक देश के 18,452 गाँवों में बिजली नहीं पहुंची थी और इन गाँवों में बिजली पहुँचाना केंद्र सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक था। अब भारत के हर गाँव में बिजली पहुँच जाने से न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। बिजली से जुड़ने वाला आखिरी गाँव लाइसंग मणिपुर के सेनापति जिले में है और विद्युतीकरण का लक्ष्य समय सीमा से 12 दिन पहले पूरा हो चुका है।









Satyagraha to Swachhagraha: A journey of a hundred years

Evoking the spirit of the Champaran Satyagraha led by Mahatma Gandhi, PM Narendra Modi addressed the National Convention of Swachhagrahis to mark the centenary celebrations of the Jan- Andolan. PM Modi addressed 20,000 Swachhagrahis at the event and honoured the work of those citizens who have transformed Swachh Bharat into a mass movement.



Moreover, in tandem with the spirit of the campaign, PM Modi also announced a series of developmental initiatives as following:

- For Water Supply and Sanitation Sector he unveiled a plaque for marking the foundation stone
 of Motijheel Project, the Bettiah Nagar Parishad Water Supply Scheme, and four Ganga Projects.
- For the Railways Sector, he laid the foundation stone for doubling of railway lines between Muzaffarpur and Sagauli, Sagauli and Valmikinagar. Through video link, he flagged off the first 12000 HP Freight Electric Locomotive, and the Champaran Humsafar Express. The Prime Minister also dedicated first phase of the Madhepura Electric Locomotive Factory to the nation.
- Foundation stones for a road lane of NH-2 in Auranagabad Bihar-Jharkhand border section, a petroleum oil lube and LPG terminal of Indian Oil Corporation Ltd at Motihari as well as LPG Plant of HPCL at Sagauli were laid by him.





सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक: 100 साल की यात्रा

महात्मा गांधी की अगुवाई में हुए चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और इस जनआंदोलन के आदर्शों और उपलब्धियों को याद किया। मोतिहारी में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री ने 20,000 स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया जिन्होंने अपने संबंधित गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट कार्य किया था।

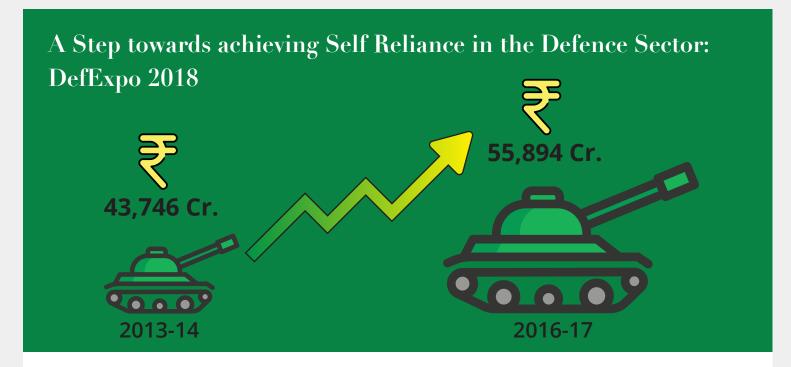


इसके साथ-साथ पीएम मोदी ने जल आपूर्ति और स्वच्छता व रेलवे समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वो हैं :--

- जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में, उन्होंने मोतीझील परियोजना, बेतिया नगर परिषद जल आपूर्ति योजना और गंगा से जुड़ी चार परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इनके प्रतीक के रूप में एक पट्टिका का अनावरण किया।
- रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर और सगौली तथा सगौली और वालमिकीनगर के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण के पिरयोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जिरए मालगाड़ी के इस्तेमाल के लिए बनाए गए 12000 अश्वशक्ति वाले पहले बिजली इंजन और चंपारण हमसफर एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसके साथ ही मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया।
- -● बिहार झारखंड सीमा सेक्शन पर औरंगाबाद में एनएच–2 के लिए एक नयी सड़क, मोतिहारी में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के एक एलपीजी टर्मिनल और ऑयल ल्यूब तथा सगौली में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी संयंत्र की आधारशिला भी रखी।







This year's DefExpo brought forward the crucial endeavours adopted by the Government led by PM Narendra Modi whose primary objective in the defence policy has been the indigenisation of defence manufacturing. In this regard PM Narendra Modi said that DefExpo "is an opportunity like none other not only to discuss India's defense requirements, but also to show-case for the first time ever in such a manner, India's own defense manufacturing capabilities to the world".

India has achieved significant progress in defense production where Indian defense production has progressively increased from Rs. 43,746 crores in 2013-14 to Rs. 55,894 crores in 2016-17. Major takeaways from the PM's speech:-

- Government's commitment to peace is just as strong as our commitment to protecting our people & our territory
- Defence Procurement Procedure has been revised with many specific provisions for stimulating growth of domestic defence industry
- Government is committed to establishing 2 Defence Industrial Corridors: 1 in Tamil Nadu &
 1 in Uttar Pradesh; the corridors will become engines of economic development & growth of defence industrial base
- Government launched the 'Innovation for Defence Excellence' scheme, which will set up Defence Innovation Hubs throughout the country
- Government resolved the issue of providing bullet proof jackets to Indian soldiers which was pending for years



Paving the roads for development of 'New India'

PMGSY crossed an important milestone with 1,52,165 rural habitations being connected by all-weather roads until March, 2018. 85% of the target achieved, the target to provide all-weather road connectivity to 1,78,184 eligible habitation has been preponed from 2022 to 2019.





डिफेंस एक्सपो 2018: रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम



इस वर्ष के डिफेंस एक्सपो में पहली बार मौजूदा सरकार के दृष्टिकोण की झलक देखने को मिली, जिसकी रक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा निर्माण का स्वदेशीकरण रहा है। डिफेंस एक्सपो के 10 वें संस्करण में इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता से घोषणा की कि यह अभूतपूर्व मौका है न केवल भारत की रक्षा आवश्यकताओं पर विचार करने का बिल्क पहली बार विश्व को भारत की अपनी निर्माण क्षमता को दिखाने का मौका भी है।

भारत ने रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। भारत के रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन क्रमशः 2013—14 में 43,746 करोड़ रुपये से बढ़कर 2016—17 में 55, 894 करोड़ रुपये का हो गया। प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य अंशः

- 🖜 सरकार जितनी शांति के लिए प्रतिबद्ध है, उतनी ही अपने नागरिकों और क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है।
- → वर्तमान में रक्षा निर्माण के विकास को गति देने के लिए सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया को कई विशिष्ट प्रावधानों के साथ संशोधित कर पारदर्शी बनाया है।
- → केंद्र दो औद्योगिक रक्षा गलियारे स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा जो आर्थिक विकास और रक्षा निर्माण को बढ़ावा देंगे।
- 🗕 प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोत्पाद योजना की शुरुआत की।
- 🖜 सरकार ने वर्षों से लंबित भारतीय सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान करने के मुद्दे को हल किया।

न्यू इंडिया में तीव्र गति से ग्रामीण सड़क निर्माण

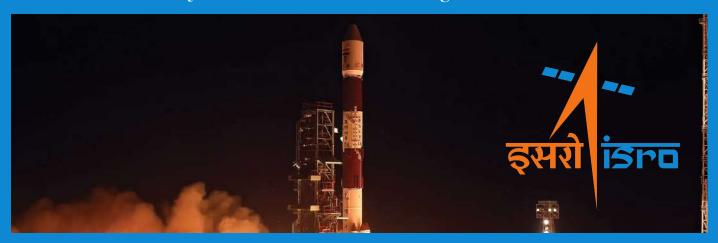


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च 2018 तक देश में लगभग 1,52,165 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है जो कि कुल बसावटों का 85% है। पहले चरण के तहत कुल 1,78,184 बसावटों को बारहमासी सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य, वर्ष 2022 से घटा कर 2019 कर दिया गया है।





ISRO successfully launches its final navigation Satellite IRNSS-11



ISRO scientists have successfully launched navigation satellite IRNSS-11 by PSLV.IRNSS -11 is the latest member of the 'Navigation with Indian Constellation (Navic) system. Navic also known as Indian regional Navigation Satellite System (IRNSS) is an independent regional navigation satellite system designed to provide information in the Indian region and 1500 km around the Indian mainland.

Harnessing the spirit of entrepreneurship: PM Modi interacts with MUDRA beneficiaries

PM Narendra Modi interacted with over 100 beneficiaries at his residence on the completion of three years of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana. The scheme has been one of the flagship initiatives of the government to promote the spirit of entrepreneurship by funding the unfunded. During the course of an informal interaction, many beneficiaries, especially women recounted their story of how the MUDRA loans have empowere them and made them self-sufficient.





Ms. Kiran Kumari, a beneficiary from Bokaro, Jharkhand,

who received a loan of Rs. 2 lakh, started her own toy and gift shop.
Earlier, she and her husband earned their livelihood selling toys as hawkers. After receiving the loan, she has been able to establish herself as a successful entrepreneur.



Ms. Munirabanu Shabbir Hussain Malek from Surat,

received a Mudra Loan of Rs.
1.77 lakh. She took LMV driving training and is now earning Rs.
25,000 per month, by driving an auto rickshaw.



Ms. Veena Devi, from Kathua District of Jammu and Kashmir

works as a weaver. She received a
Mudra loan of
Rs. 1 lakh. She is now one of the
leading manufacturers of
Pashmina shawls in her area.









इसरों ने नेविगेशन उपग्रह आईआरएनएसएस-1आई का सफल परीक्षण किया



इसरों ने पीएसएलवी—सी41 के जिरए आईआरएनएसएस—1आई नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह सात दिशासूचक उपग्रहों के समूह का हिस्सा है। एनएवी—आईसी, जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसका निर्माण भारतीय क्षेत्र में स्थिति की जानकारी प्रदान करने और भारतीय भूमि के करीब 1500 किलोमीटर क्षेत्र में नजर रखने और स्थिति से जुड़ी सटीक सूचना देने के लिए डिजाइन किया गया है।

उद्यमिता को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मिले पीएम



प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तीन वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर 100 से अधिक लाभार्थियों से बातचीत की। अप्रैल 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत आसान ऋण प्रदान करके युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने वाली सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। इस योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली जिससे महिलाओं समेत पिछड़े और वंचित वर्गों को भी कई फायदे मिले। अनौपचारिक मुलाकात के दौरान कई लाभार्थियों, विशेषकर महिला लाभार्थियों, ने बताया कि मुद्रा ऋण से उनका जीवन किस प्रकार बेहतर हुआ है? कैसे मुद्रा योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है:





बोकारों की सुश्री किरण कुमारी को 2 लाख रूपये का ऋण मिला था। उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से उन्होंने अपनी खिलौने और उपहार दुकान की शुरूआत की। इसके पहले वे और उनके पित फेरी लगाकर खिलौने बेचते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। ऋण मिलने के पश्चात वे एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हो गई हैं।



सूरत की सुश्री मुनिराबानू शब्बीर हुसैन मलेक को 1.77 लाख रुपये का मुद्रा ऋण प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। ऑटोरिक्शा चलाकर वे अब प्रति महीने 25 हजार रुपये कमा रही हैं।



जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले की **सुश्री वीना देवी** बुनकर का कार्य करती हैं। उन्हें 1 लाख रुपये का मुद्रा ऋण मिला। अब वे अपने क्षेत्र में पश्मीना शॉल की प्रमुख निर्माता हो गई हैं।





Fugitive Economic Offenders Ordinance: A decisive endeavor by the government to combat economic malpractice in the society

In a move to combat the string of economic malpractices that have fraught our economic scenario, the Union Cabinet on April 21 2018 approved the Fugitive Economic Offenders Ordinance which is targeted at high-profile offenders in financial malpractices.

The objective of the Ordinance is to prevent economic offenders evade national laws by remaining outside the jurisdiction of Indian courts after committing economic offences. The ambit of the term economic offences include those that are defined under the Indian Penal Code, the Prevention of Corruption Act, the SEBI Act, the Customs Act, the Companies Act, Limited Liability Partnership Act and the Insolvency and Bankruptcy Code.

Moreover the ordinance covers economic offences that have a value of Rs 100 crore or more where the offenders commit economic offences as mentioned under the above scope. The Ordinance further makes provisions for a court ('Special Court' under the Prevention of Money-Laundering Act 2002) to declare a person as a Fugitive Economic Offender.



Fugitive economic offenders include all those individuals against whom an arrest warrant has been issued for committing economic offences and have left India to avoid criminal prosecution and refuses to return to the country to face criminal prosecution.

A unique feature of the Ordinance is that under this it would lay down measures that would allow the Indian Government to confiscate the property of economic offenders absconding from India until they submit themselves to the jurisdiction of the appropriate legal forum.

Under the ordinance on economic offenders, the following provisions has been laid out which acts as a significant step towards providing an effective, expeditious and constitutionally permissible deterrent to ensure that such economic malpractices are curtailed. The provisions are as follows:-

6

- 1 Presentation of application before the special court for a declaration that an individual is a Fugitive Economic Offender.
- 2 Attachment of Fugitive Economic Offender's property along with the proceeds of crime.
- 3 Issue of notice by 'Special Court' to the alleged individual.
- Confiscation of alleged individual's property and crime proceeds.
- Disentitlement of the alleged individual from defending any civil claim.
- Appointment of an administrator to manage and dispose of the confiscated property.





भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018: आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए मोदी सरकार की महत्वपूर्ण पहल

देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख देने वाले एक के बाद एक आर्थिक अपराधों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय कैंबिनेट ने 21 अप्रैल 2018 को भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश—2018 को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश विदेशों में छिपे हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों को कानून की पकड़ में लाने के लिए और भविष्य में आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए लाया गया है।

इस अध्यादेश का उद्देश्य ऐसे आर्थिक अपराधों की रोकथाम है जिसमें अपराधी आर्थिक अपराध करके देश के कानून की पकड़ से बचने के लिए विदेश भाग जाता है। 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके खिलाफ भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा अनुसूचित अपराधों के तहत नोटिस जारी किया गया है और जिसने सजा से बचने के लिए देश छोड़ दिया है, या फिर वो विदेश में कहीं छिपा बैठा है और भारत आकर अपने खिलाफ अदालती कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर रहा है।

भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक—2018 से अधिकारियों को देश छोड़कर भाग गए भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति अटैच करने या जब्त करने का अधिकार मिलेगा। अध्यादेश के तहत भारत या विदेशों में अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की शीघ्र करने के लिए एक विशेष मंच बनाया जाएगा। यह मंच भगोड़े अपराधियों की भारत वापसी के लिए दबाव बनाएगा, जिससे अपराध के मामलों में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में उनके खिलाफ मुकदमा चलाना आसान होगा।



अध्यादेश में किसी व्यक्ति को आर्थिक अपराध का भगोड़ा घोषित करने के लिए धनशोधन कानून 2002 के तहत विशेष अदालत का प्रावधान किया गया है। इस अध्यादेश में ऐसे मामलों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए और अदालतों को मामलों के बोझ से बचाने के लिए इस अध्यादेश के दायरे में सिर्फ उन्हीं मामलों को शामिल किया गया है, जिनका कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।



इस अध्यादेश में निम्नलिखित प्रावधान हैं

किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष अदालत को में आवेदन प्रस्तुत करना।
विशेष अदालत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी कर सकती है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसी भारतीय अदालत या अधिकरण में दीवानी दावा पेश नहीं कर सकता है।





GEDT 24 STUC COLL

Photo Gallery

PM Modi handing over the cheque under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana







